CHAPTER-IV

AIACE IN MEDIA

पेंशन ब्याज भुगतान में हो रहे विलंब को लेकर कोल इंडिया के रिटार्यड अधिकारियों ने की सरकार से हस्तक्षेप की मांग

भाषा। 16 अगस्त

नई दिल्ली : सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के एक संगठन ने उपक्रम की पेंशन योजना को अंतिम रूप दिये जाने में हुई देरी के चलते कर्मचारियों को ब्याज का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित मामले में सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एक्सीक्यूटिव्स (एआईएसीई) के प्रधान महासचिव पीके सिंह राठौड़ ने सरकार को भेजे एक पत्र में कहा, हमारा संगठन कोल इंडिया के निदेशक मंडल स्तर के और इससे निचले स्तर के अधिकारियों के सेवानिवृत्ति लाभ के तौर पर सीआईएल कार्यकारी सुनिश्चित योगदान पेंशन योजना-2007 के निपटान में हुई देरी के चलते एक जनवरी 2007 से क्षतिपूर्ति दर पर ब्याज के भुगतान को शीघ्रता से मंजूरी दिये जाने के संदर्भ में आपसे हस्तक्षेप की मांग करता है। उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2007 से 31 मार्च 2020 तक कोल इंडिया के करीब 10 हजार अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। दुर्भाज्ञ से इनमें से कई अधिकारियों की बिना सेवानिवृत्ति और योजना के ब्याज लाभ पाये मृत्यु हो चुकी है। कोल इंडिया और इसकी अनुषंगियों ने योजना के कियान्वयन से पहले ही मर चुके अधिकारियों को लेकर नामितों की पहचान नहीं की है। ऐसे में उनके हिस्से का कोष सीआईएल और अनुषंगी कंपनियों के संदेहास्पद खाते में पड़ा है। राठौड़ ने कहा, कोल इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन से हमारे लगातार संवाद से ज्ञात हुआ कि ब्याज घटक के भुगतान के मुद्दे को आवश्यक निर्देश के लिये कोयला मंत्रालय के पास भेजा जा चुका है। अभी भी इस मुद्दे का हल नहीं निकल पाया है।

दैनिक भास्कर

कोरबा 12-08-2021

कोरबा

आंदोलन • सेवानिवृत्त अधिकारी 16 अगस्त से सीएमपीएफ कार्यालय के सामने करेंगे आमरण अनशन

विसंगति के चलते कर्मचारियों को मिल रही कम पेंशन, एआईसीपीए करेगा आंदोलन

भास्कर न्यूज | कोरबा

सेवानिवृत्त कोयला अधिकारी व कर्मचारियों की पेंशन विसंगति को लेकर ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन (एआईसीपीए) व ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एक्सक्यूटिव (एआईएसीई) मिलकर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए अलग-अलग कोल कंपनियों के पेंशनर संगठन को भी एकजुट किया जा रहा है। पेंशनरों की समस्या के निराकरण के लिए कोल इंडिया प्रबंधन, सीएमपीएफ चेयरमैन के अलावा मंत्रालय को भी पत्र लिखा गया है। संगठन का कहना है कि कोयला कंपनी से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन के अनुरूप पेंशन नहीं दिया जा रहा है। इसमें विसंगतियों के साथ ही त्रुटिपूर्ण गणना के चलते भी पेंशनर को समस्या हो रही है। नए वेतनमान के अनुरूप पेंशन का निर्धारण किया जाना था, जो नहीं हुआ। इसी तरह वर्ष 2007 से पहले सेवानिवृत्त वाले कर्मचारी व अधिकारियों का पेंशन भी काफी कम है। प्रबंधन के समक्ष कई बार पेंशन बढ़ाने की मांग की गई है। लेकिन अब तक मांग पूरा नहीं हुई है। इस बार 2006 में सेवानिवृत्त होने वाले कोल पेंशनर एचके चौधरी पेंशन विसंगति व गलत गणना को लेकर 16 अगस्त से सीएमपीएफ मुख्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू करेंगे। जिसका समर्थन करते हुए ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एक्जीक्यूटिव संघ व ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्य भी आंदोलन में शामिल होंगे। मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला संगठन ने किया है।

एकजुटता दिखाते हुए कोल पेंशनर व अधिकारी संगठन के सदस्य ।

पेंशन बढ़ोतरी के अलावा अन्य मांगे भी निराकृत नहीं

पेंशन बढ़ोतरी के अलावा मृत पेंशनर्स के आश्रित पत्नी का पेंशन जल्द शुरू कराने की मांग भी प्रमुख मुद्दा है। पेंशनर्स की मृत्यु के बाद उनके आश्रित पत्नी का पेंशन शुरु करने कई तरह की कठिनाई होती है। प्रबंधन के सामने संगठन ने पहले भी इस समस्या को लेकर प्रबंधन के समक्ष रहा था। 5 माह पहले भी इसको लेकर आंदोलन किया था। लेकिन समस्या बनी हुई है।

इधर पेंशन फंड में कमी की चिंता भी सता रही है

एक तरफ कोयला अधिकारी व कर्मचारियों के पेंशन भुगतान को लेकर कई तरह की समस्याएं हैं। अब फिर से पेंशन फंड को लेकर चिंता सता रही है। पूर्व में पेंशन फंड में सुधार के लिए कोयले पर प्रति टन 10 रुपए सेस लगाने की सहमति दी गई थी। लेकिन, इसके बाद भी समस्या हो रही है। इधर पेंशन संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए अगले माह बैठक ट्रस्टी बोर्ड की बैठक की संभावना बनी हुई है।

आंदोलन की चेतावनी के बाद सीएमपीएफ चर्चा के लिए बुलावा: इधर सीएमपीएफ कार्यालय के सामने आंदोलन की चेतावनी के बाद कोल पेंशनर्स की समस्याओं के निराकरण को लेकर पेंशनर व कोयला अधिकारी संगठन के प्रतिनिधियों को बुलाया है। संघ के प्रधान महासचिव पीके सिंह राठौर ने कहा कि मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो हर हाल में आंदोलन होना है, इसकी तैयारी कर ली गई है। कोल पेंशनरों की समस्याओं को लेकर कोल कंपनी, सीएमपीएफ प्रबंधन से कई बार पत्राचार किया गया।